gical phenomena particularly using satellite observations, earth's near environment including atmospheric pollution.

Scientists from different universities and institutions are being provided support to carry out observations using the MST Radar facility in the area of atmospheric dynamics and related phenomena.

Department of Space is providing necessary support for the development of satellite payloads at national laboratories/institutions for space science research. Recently an experiment of National Physical Laboratory (NPL) for investigating F-region ionospheric phenomena has been carried out on-board SROSS-C satellite launched by ISRO.

Department of Space has been funding the *maintenance and operation of a chain of multi*wavelength and BUV radiometer stations at National Physical Laboratory (NPL), New Delhi, Mysore University, Andhra University, Poona University, Centre for Earth Science Studies (CESS), Trivandrum for studies related to variation of atmospheric aerosol loading and ultraviolet fluxes received on the surface.

Duplicate automobile parts

@4397-A. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:
SHRI V. NARAYANASAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of the automobile parts sold in the markets are the immitations of the originals;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) whether Government have taken any measure to check such nefarious activities?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) and (b) The manufacture and sale of spurious goods, including automobile parts, in the market gets reported from time to time in the press and by various consumer fora. However, no specific report or complaint has been received by this Ministry in the recent past.

(c) Does not arise.

Import licence to Meltron

@@4397-B. SHRI SATISH PRADHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government had issued import licence to Maharashtra Electronic Corp. Ltd. (Meltron) to import multi-channel voice logging recorder; if so, what is the foreign exchange amount involved;

(b) whether multi-channel voice logging recorders (MVRLS) are used by institutions specifically by Defence and Air Port authorities;

(c) whether before granting the licence Government has verified placement of firm orders by the users of MVRLS, if so the reasons therefor; and

(d) whether it is a fact that sixty eight pieces of MVRLS valued at Rs. 186 crores involving foreign exchange are accumulating dust?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) No such import licence has been issued to Maharashtra Electronic Corp. Ltd. (Meltron) under the current Exports and Imports policy, 1992—97 effetive from 1-4-1992.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise in view of (a) above.

(d) The Government have no such information.

फलों, सब्जियों और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के संबंध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

@@@4397-(ख). श्रीमती सुषमा स्वराज: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में इस आशय की सिफारिश की है कि देश में फलों, सब्जियों और उनसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को

@ Previously Unstarred Question 3534, transferred from 23-8-1993.

@@ Previously Unstarred Question 3744, transferred from 24-8-93.

बढ़ावा देने की पर्याप्त क्षमता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समिति ने इस क्षमता के उपयोग के संबंध में कतिपय सिफारिशें की हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने और खाद्य प्रसंस्करण एककों के विस्तार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या यह भी सच है कि उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3,000 करोड़ रूपए से 4,000 करोड़ रूपए तक है हर वर्ष नष्ट हो जाती है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अनावश्यक हानि को रोकने के लिए देश की परिस्थितियों, सामर्थ्य व साधनों के तहत क्या-क्या उपाय किए जा रहे है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ताजे फल और संसाधित खाद्य पदार्थों के बारे में गठित एक्सटीम फोकस ग्रुप ने अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें शामिल है : कम ब्याज दरों पर वित्त का प्रावधान, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना, रियायती, दरों पर विद्युत उपलब्ध कराना व्यवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार भाड़ा दरों में कमी, अंगूर रक्षक कागज के शुल्क मुक्त आयात का प्रावधान, पैकजिंग में सुधार आदि ।

(घ) और (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को 46 करोड़ रू० का आबंटन किया गया है जिसे उत्पादन तथा प्रसंस्करण यथा, प्रशीतन गृहों तथा प्रसंस्करण सुविधाओं, प्रशीतित परिवहन, विपणन नेटवर्क श्रमिकी की प्रशिक्षण, फलों, सब्जियों, कुक्कुरमुत्तों, मांस, अंडा तथा कुक्कुट, तथा ट्रना और अन्य मत्स्य प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं का विकास जैसी व्यवस्थापना को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है । इन प्रयासों की कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडी) से भी बढ़ावा मिल रहा है ।

(च) और (छ) हालांकि, समुचित भंडारण सुविधाओं की कमी की वजह से फलों और सब्जियों को हुई हानि का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, फिर भी योजना आयोग के भूत पूर्व सदस्य डा० एम० एस० स्वामीनाथन की अध्यक्षता में मई 1981 में खराब होने वाली कृषि मदों के बारे में गठित एक दल की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया था कि कतिपय फलों और सब्जियों का लगभग 40% भाग, इन उत्पादों के लिए फसल पश्चात समुचित व्यवस्थापना सुविधाओं और संसाधन सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण बेकार हो जाता है । फलों तथा सब्जियों और खाद्य मदों के प्रसंस्करण की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने इन उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विविध कदम उठाए है ।

@@@@पूर्वत: तारांकित प्रश्न 3906, 28 अगस्त, 1993 से स्थानान्तरित ।

Revival of Kribhco

@@@@ 4397-D. SHRI DIGVIJAY SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is fact that KRIBHCO is facing sickness due to its heavy investment with the finance company resulting in lack of growth opportunity;, and

(b) if so, what steps are contemplated by the Government to revive it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Uniform Farm Marketing Policy

$4397-E. DR. NAUNIHAL SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal for an uniform farm produce marketing law for the agro-base industry of the country, if so, the details thereof;

(b) whether Government are aware that at present each State and Union Territory has its own farm produce marketing law and imposes varying rates of taxes on the dealers and buyers besides imposing stock limits, if so, the details thereof;

(c) whether Government are aware that this offer results in multiple taxation and avoidable harassment to the agro-base and agro-processing industry; and

(d) whether Government have taken any steps to rectify the maladies in the field of farm produce marketing, if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE

@@@@Previously Unstarred Question 4065, transferred from 25-8-1993.

$Previously Unstarred Question 4422, transferred from 27-8-1993.